



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 फाल्गुन 1941 (श0)
(सं0 पटना 211) पटना, मंगलवार, 17 मार्च 2020

सं0 1प/स्था0-15-01/2019/5966/पं0रा0
पंचायती राज विभाग

सेवा मे,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा,

वित्त विभाग, बिहार।

दिनांक 19 सितम्बर 2019

विषय:-

“बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग” नियमावली, 2019 के गठन के फलस्वरूप बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373 (तीन सौ तिहत्तर), वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 174(एक सौ चौहत्तर), जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 41 (इकतालीस) एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी(पंचायती राज) के 01(एक) कुल 589 (पांच सौ नवासी) पदों के सृजन एवं अनुमानित वार्षिक व्यय भार कुल ₹27,98,45,376.00 (सताईस करोड़ अनठानवे लाख पैंतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर रुपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत स्थायी रूप से स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:-

स्वीकृत।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 31, 59 तथा 86 में अंकित प्रावधानों एवं विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित योजनाओं से संबंधित राशि के नियमानुकूल प्रबंधन एवं व्यय हेतु एक कुशल एवं सशक्त अंकेक्षण संवर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 01.02.2019 में मद संख्या-08 के रूप में बिहार पंचायती राज अंकेक्षण संवर्ग नियमावली, 2019 स्वीकृत एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 1186, दिनांक 14.02.2019 के द्वारा अधिसूचित है।

3. सेवा संवर्ग नियमावली गठन के फलस्वरूप राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यथा- कुल 8386 ग्राम पंचायत, 8386 ग्राम कचहरी, 534 पंचायत समिति तथा 38 जिला परिषद् के वित्तीय प्रबंधन को सशक्त बनाने एवं वार्षिक अंकेक्षण कार्यों के सफल निष्पादन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 28.06.2019 की बैठक में दी गयी स्वीकृति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के अंकेक्षक (पंचायती राज) के 373 (तीन सौ तिहत्तर), वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 174(एक सौ चौहत्तर), जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) के 41(इकतालीस) एवं मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी(पंचायती राज) के 01(एक) कुल 589 (पांच सौ नवासी) पदों के

सृजन एवं अनुमानित वार्षिक व्यय भार कुल ₹27,98,45,376.00 (सत्ताईस करोड़ अनठानवे लाख पैंतालीस हजार तीन सौ छिहत्तर रुपये) मात्र का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अन्तर्गत स्थायी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है (व्यय विवरणी संलग्न)।

4. (क) सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	पदों की स्थिति	वेतन स्तर	ग्रेड पे	पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अंकेक्षक (पंचायती राज)	मूल कोटि	अराजपत्रित	लेवल-5	₹2800/-	373
2	वरीय अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज)	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित	लेवल-6	₹4200/-	174
3	जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित	लेवल-7	₹4600/-	41
4	मुख्य अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित	लेवल-8	₹4800/-	01
				कुल :-		589

(ख) जिलावार पदों की संख्या (अनुसूची-क' के रूप में) संलग्न है।

5. बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा के उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप पदों एवं अन्य खर्चों पर होने वाला व्ययभार का वहन राज्य सरकार के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत किया जायेगा:-

(क) क्षेत्रीय जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग के कार्यालयों में अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों के व्यय का वहन "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना"-विपत्र कोड-16-2515000010003" के अन्तर्गत किया जायेगा। इस शीर्ष से निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला अंकेक्षण अधिकारी (पंचायती राज) होंगे।

(ख) मुख्यालय (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) के अंकेक्षण प्रशाखा में अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों के व्यय का वहन "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0001-मुख्यालय पंचायत स्थापना"-विपत्र कोड-16-2515000010001" के अन्तर्गत किया जायेगा। इस शीर्ष से निकासी की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मुख्यालय (पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना) के नामित/प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे।

6. पद सृजन के फलस्वरूप सृजित/स्वीकृत पदों के विरुद्ध नयी नियुक्ति होने तक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित प्रावधानों के आलोक में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों/संस्थाओं से सेवानिवृत्त अंकेक्षक/अंकेक्षण पदाधिकारियों की सेवा संविदा के आधार पर ली जायेगी।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.08.2019 की बैठक के मद संख्या-05 में स्वीकृत है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 211-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>